

इस धंक में

1. दि. वि. छात्रसंघ चुनाव
2. सम्पादकीय
3. दक्षिण अफ्रीका : अब मंजिल दूर नहीं
6. साक्षात्कार
7. New Education Policy: analysis
8. Book Review
10. Sri Lanka
12. 'SEIL' A Project Of National Integration.

## राष्ट्रीय छात्र शक्ति

: सम्पादक :  
संजय सत्यार्थी

सम्पादकीय सहकर्मी  
राकेश सिन्हा, संजय चौधरी

प्रकाशन कार्यालय  
प्र० भा० विद्यार्थी परिषद  
16/3676, रंगरपुरा,  
हरध्यान सिंह मार्ग  
करोलबाग, नई दिल्ली-5  
दूरभाष 5728215

## दि० वि० वि० छात्रसंघ चुनाव: परिषद की विजय अपूर्ण

30 अगस्त 1986; गहराती शाम। पंचकुइयाँ रोड पर स्थित NDMC की लाल इमारत के चारों ओर भूँड-के-भूँड खड़े लोग। वर्दीधारी पुलिस। शोर मचाता छात्र-समूह। रुकती-ठिठकती, उत्सुकता और खीज भरी निगाह डालती ट्रैफिक। इमारत के भीतर चल रही मतगणना का परिणाम जानने को आतुर फोन की घंटियाँ। समय बीतने के साथ-साथ उत्तरोत्तर आवेशित होता वातावरण। भीतर से उड़ती-पड़ती खबरें आधी-सब आधी भूँड। अपवाहों के कारण माहौल में सनसनाहट। और इन सब के बीच लगभग 8 बजे (शाम) परिणाम की घोषणा।

लोग ठीक से संभल भी नहीं पाये थे कि हिंसा फूट पड़ी। दरअसल पिछले वर्षों की तुलना में इसबार छात्रसंघ चुनाव इतना पेचीदा था कि माहौल की सनसनाहट हिंसा में बदल गई। बोललें चलीं, पत्थर चले, पुलिस की लाठियाँ चलीं, प्रभुगंस के गोले चले। परिषद के संगठन मंत्री श्री नन्दकिशोर जोशी सहित कई कार्यकर्ता घायल हुए।

परिणाम यों था—वि० वि० छात्रसंघ के चार महत्वपूर्ण पदों में से दो पर परिषद् कार्यकर्ता विजयी रहे। विद्यार्थी परिषद् के नरेन्द्र टंडन और नीना सचदेवा क्रमशः सचिव व सहसचिव के लिए निर्वाचित घोषित हुए। अध्यक्ष पद के लिए परिषद् उम्मीदवार राकेश सिन्हा और उपाध्यक्ष पद के परिषद् उम्मीदवार प्राथीप सूद क्रमशः मदन सिंह विष्ट और अंजू मलहोत्रा से हार गए।

कई वर्षों के बाद इस वर्ष विद्यार्थी परिषद् ने वि० वि० छात्रसंघ चुनाव अकेले लड़ा था। सहयोगी संगठन ज० वि० मों का बाहर से समर्थन प्राप्त था।

परिषद् के उम्मीदवारों ने पिछले कई वर्षों से चले आ रहे छोटे मुद्दों के साथ छात्रसंघ को फिर से परिभाषित करने की बात भी कही। प्रचार के लिए कम समय होने के कारण ठीक से बात नहीं रखी जा सकी। छात्र समुदाय भाँसे में आ गया। महत्वपूर्ण चार सीटों में से दो सीटें परिषद् के हाथ से निकल गयीं। हाँ कांग्रेस की छिछोरी राजनीति का जो प्रकोप पिछले वर्ष बढ़ा था, वह समाप्त प्राय हो गया।

## सम्पादकीय

दोस्तों,

फ्रांस के विख्यात लेखक विक्टर ह्यूगो ने कहा था—'दुनिया में उस विचार से मजबूत और कुछ भी नहीं है, जिस विचार का मूहूर्त आ गया हो।' राष्ट्रीय छात्र शक्ति को फिर से प्रारम्भ करने की बात काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज यह आपके सामने है, शायद यही इसका मूहूर्त था। नया कलेवर, नया रूप, नयी टीम—सब-कुछ नया। परन्तु नाम और उद्देश्य वही हैं—छात्र-जगत की हलचल से शेष समाज को परिचित कराना; शेष समाज की भावनाओं को छात्र-छात्राओं तक पहुँचाना।

पत्रिका की शुरुआत बड़े संवेदनशील माहौल में हो रही है। देश में नित नयी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, नये हादसों हो रहे हैं। और हम इन हादसों की चर्चा भर करते हैं। चिन्ता बिल्कुल नहीं। चर्चा ऐसी जैसे पानी के बुलबुले हों जो सतह पर इकट्ठे उगते हैं तो सगता है मानों पानी खील गया। परन्तु क्षणभर बाद जब गायब होते हैं तो सब समाप्त जान पड़ता है। समाज के प्रति, देश के प्रति, संस्थाओं के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रति बढताएँ स्थलित होती जा रही हैं। हम भारत के युवा लोग भारतीय जनमानस से कहीं दूर खड़े यहाँ हो रहे हादसों को ऐसे देखते हैं मानों फिल्म देख रहे हों। आतंकवाद की आँच में भुलसते पंजाब के लोग, गोरखालैंड के बिद्रोही, श्रीलंका में अपने सगे सम्बन्धियों पर हो रहे अत्याचार से चिन्तित तामिल समुदाय, मध्यभारत में जुलम सहते हरिजन-वनवासी-सब हमें पराये—अजनबी लगते हैं। अपने स्वप्न संसार में हम स्वयं को सुरक्षित समझते हैं; भौतिकता के मोग का आनन्द उठाना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकताएँ हम से शुरु होकर 'हम' पर ही समाप्त हो जाती हैं।

परन्तु नहीं। हम में से हर कोई ऐसा नहीं है। हमारे बीच के ही कई नौजवानों की प्राथमिकता सूची में देश समाज का नाम सबसे ऊपर है। देश के किसी कोने में उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय और अविवेकता से उन्हें दर्द महसूस होता है। उन्होंने देश को सँवारने का, बनाने का, पुनर्निर्माण का व्रत ले रखा है। उनकी बात रखने के लिए भी इस पत्रिका की शुरुआत हो रही है। आप पाठकों के साथ उनका संवाद स्थापित हो सके, यह भी इस पत्रिका की सफलता की एक कसौटी होगी। छात्रोपयोगी अन्य जानकारियों से आपको अवगत कराते रहने का भी हमारा प्रयत्न रहेगा।

आप इसे पढ़ें। इसके लिए लिखें। अपनी टिपणियाँ भेजें। आसपास की छात्र-युवा गतिविधियों की रिपोर्ट भेजें। सबका स्वागत है। यह छात्रों द्वारा, छात्रों के लिए, छात्रों की पत्रिका है—उम सब के समवेत संकल्प का प्रतीक-पत्र।

सं० स०

## दक्षिण अफ्रीका—अब मंजिल दूर नहीं

प्रसव वेदना से तड़पती, लस्त-पस्त हालत में एक महिला को अस्पताल लाया जाता है, डाक्टर उसे एडमिट करने से इन्कार कर देते हैं। परिचर्या के अभाव में वह महिला सामने की फुटपाथ पर मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि उस महिला की चमड़ी 'काली' है। पार्क में खेलते बच्चों को देखकर एक अशोध बालक उनके साथ खेलने चला जाता है। वह नहीं जानता कि उसके माता-पिता को उसके इस 'अनजाने अपराध' के लिए जुर्माना भरना पड़ा है। प्रतिभाशाली छात्र एलबर्ट रोजो को अपने देश के एक प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उसका रंग 'काला' है। आज से चौबीस साल पहले 'नेल्सन मांडेला' नामक नौजवान अपनी छोटी गुड़िया सी बेटी को बचपन का लाड़-दुलार न दे सका। उसे जेल जाना पड़ा क्योंकि वह रंगभेद का विरोधी था। नस्लवादी जूनन के ये कुछ नमूने 'स्वतंत्रता, समानता, और न्याय' का दंभ भरने वाली दुनिया के ही एक भाग की कहानी है। आज दुनिया का छात्र-समुदाय जिस रोड्स स्कालरशिप (Rhodes scholarship) को पाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है क्या वह नहीं जानता कि जिस स्वनामधन्य 'सिसिल जॉन रोड्स (Cecil John Rhodes) के नाम पर यह छात्रवृत्ति है, वह नस्लवाद और रंगभेद की नीति का पितामह था। जो समूचे विश्व में 'एंग्लोसैक्सन' जाति की सर्वोच्चता का परम पत्रपाती और 'केप से काहिरा तक को' ब्रितानी रंग में रंगने का स्वप्न देखा करता था।

अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम छोर पर बसा एक देश है जिसे दुनिया 'दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य' के नाम से जानती है। चार प्रांतों (केप, नेटाल, ट्रांसवाल) में विभाजित यह देश साढ़े चार लाख वर्गमील में फैला है। अच्छी जलवायु, ऊंची-चौड़ी समतल भूमि और असाधारण प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए दक्षिण अफ्रीका मशहूर है।

प्राकृतिक सम्पदाओं खासकर खनिज पदार्थों की तो बात ही क्या? सोना, हीरा, यूरेनियम, प्लैटिनम, जैसे बहुमूल्य वस्तुओं का उत्पादक और शायद सबसे बड़ा निर्यातक है यह देश।

परन्तु इस अकूत वैभव का वहाँ के बहुसंख्यक मूल निवासियों के लिए कोई अर्थ नहीं। देश की कुल 3 करोड़ आबादी में 67% 'काले', 19% 'गोरे', और करीब 14% 'भूरे' व 'एशियाई मूल' के लोग हैं। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से यहाँ 'डच' लोगों का आना-जाना और बाद में बसना प्रारम्भ हुआ। कालान्तर में यह भूभाग अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आ गया। सन् 1910 में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मिलाकर 'दक्षिण अफ्रीकी संघ' की स्थापना हुई। तबसे लगातार यहाँ 'अल्पसंख्यक गोरो' का शासन है। सन् 1961 तक दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रकुल का सदस्य था, और ब्रिटेन की महारानी यहाँ की राष्ट्राध्यक्ष थीं। 1961 के बाद से यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। जिसमें 'काले' लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है। जो इस देश का राज्याध्यक्ष माना जाता है। वैसे शासन की पूरी जवाबदेही प्रधानमंत्री की होती है।

वैसे तो दूसरे महायुद्ध के बाद ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद का ढांचा लड़खड़ा गया था। परन्तु सन् 1947 में अंग्रेजी राज (ताज) के सबसे बहुमूल्य जवाहिरात के निकलते ही मानों आजाद होने की होड़ लग गई। एक-एक कर अनेक देश आजाद हुए। साम्राज्यवाद की काली-धिनीनी चादर सिमटती गयी, फटती गयी। परन्तु अफ्रीका महादेश के कुछ हिस्सों में साम्राज्यवाद कायम रह गया। 'नस्लवाद और रंगभेद' इसी साम्राज्यवाद का परिवर्तित और नवीन संस्करण है। यह वही दक्षिण अफ्रीका है जहाँ महात्मा गांधी ने 'सत्य, न्याय और अहिंसा' के अपने हथियार पर धार चढ़ाई थी। भारत अपनी आजादी की 39 वीं वर्षगांठ मना चुका है, दक्षिण

शेष पृष्ठ 5 पर

परन्तु इस चुनाव ने विद्यार्थी परिषद् के सहयोगी संगठनों की संगठनात्मक दृष्टि में घाई कमजोरियों को एकदम से उजागर कर दिया। पिछले कई वर्षों (खासकर दो-तीन वर्षों) से ज. वि. मो. के साथ जुड़े एक खास गिरोह की संगठन विरोधी हरकतों से कार्यकर्ता परेशान हो रहे थे। लोक-लिहाज के कारण नेतृत्व बराबर उनकी अपराधिक हरकतों पर पर्दा डालने का प्रयास करता रहा। परन्तु इस वर्ष यह गिरोह बेनकाब हो गया। विश्वविद्यालय की राजनीति में इस तथाकथित तीसरी शक्ति का सिरमौर बेशक कांग्रेस के बागी लोग रहे हों परन्तु इस गिरोह की मुख्य ताकत और आधार वे ही लोग थे जो 29 अगस्त 1986 तक विद्यार्थी परिषद् और सहयोगी संस्थाओं के शुभचिन्तक (?) माने जाते थे। चुनाव प्रचार के दौरान अथवा परिणाम घोषित होने बाद की हिसा में भी इस गिरोह ने परिषद् कार्यकर्ताओं के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई।

ऐसे अंतरिक प्रतिरोधों के बावजूद परिषद् कार्यकर्ताओं की दो सीटों पर विजय का महत्व काफी बढ़ जाता है। आने वाला समय छात्र युवा-गतिविधियों की दृष्टि से काफी महत्व का है। अगले दो-तीन वर्षों में (शायद पहले भी) काफी हलचल होने की संभावना है। सन् 1974 को गुजरे एक दशक से ज्यादा हो गया है। देश में असंतोष बढ़ रहा है। नई सरकार की विफलता के कारण परिवर्तन की चाह भी बढ़ती जा रही है। फिर से एक बार तूफान आने वाला है। संकट की इस घड़ी में भारतीय छात्र-शक्ति का आवाहन करने और इसे सही दिशा देने के लिए परिषद् कार्यकर्ताओं का विश्वविद्यालय के छात्र-समुदाय के साथ सक्रिय-सम्पर्क आवश्यक है। छात्रसंघ इसके लिए एक बेहतर और

प्रभावी मंच है। हमें देखना चाहिए कि इस पर अवसरवादी और स्वार्थी तत्वों का कब्जा न हो।

दि. वि. छात्र संघ के नवनिर्वाचित सचिव नरेन्द्र टंडन ने अपने आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए दो बातों पर ज्यादा जोर दिया—“पहला कि विश्व-विद्यालय में इस बात की मुनिश्चित व्यवस्था हो जिससे छात्रों के रोजमर्रा की शिकायतों का समाधान प्रविलम्ब हो जाए। आगे दिन विश्वविद्यालय अधिकारियों की लापरवाही और आलस्य के कारण छात्रों को छोटे-मोटे कामों के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। जिससे उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। पुराने कालेजों के भवनों की मरम्मत, प्रयोगशालाओं का रखरखाव, छात्रवासों की कमी, कॉपियों की जाँच में घाँघली, आदि कई समस्याएँ सामने आई हैं। छात्रसंघ के माध्यम से हम इनके स्थायी समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी बात जो बराबर महत्व की है। छात्र राजनीति को रचनात्मक दिशा देना और देश समाज की से समस्याओं को जोड़ना। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय जो भारतीय छात्र-आन्दोलन का अग्रगण्य रहा है, अपने दायित्वों से उदासीन नहीं हो सकता। छात्रसंघ की भूमिका को पुनःपरिभाषित करने की जो बात हम कहते रहे हैं उसका तात्पर्य यही है।”

नवनिर्वाचित सचिव द्वारा आत्मविश्वास और पूरी जिम्मेवारी के साथ दिए गए इन वक्तव्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में दि. वि. छात्रसंघ की कार्य प्रणाली में काफी निखार आएगा छात्रसंघ और छात्र समुदाय के संबंध परस्पर प्रगाढ़ होंगे। देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

### छपते-छपते

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव श्री नरेन्द्र टंडन ने पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर विश्वविद्यालय अधिकारियों से वार्ता की। अंततः आन्दोलन का रास्ता अस्तित्वरूप में पड़ा। 23 सितम्बर को कुलपति कार्यालय पर परिषद् के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर हजारों छात्रों का हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र कुलपति को दिया। पुनर्मूल्यांकन फीस छात्रों को वापस किया जाए एवं परीक्षाफल से असंतुष्ट

छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएँ फिर से जांची जाएं। तत्काल कुलपति ने एक कमिटी का गठन करने की मांग स्वीकार कर ली जिसमें विशिष्ट समस्याएँ रखी जाएगी। बातचीत एवं संघर्ष का दौर चल रहा है।

मोतीलाल कॉलेज में छात्रों ने संघर्ष शुरू किया है। परिषद् छात्रों के संघर्ष में अपना समर्थन देने का फैसला लिया है।

अफ्रीका में हैवान नस्लवाद अबतक ताण्डव कर रहा है। पिछले 76 वर्षों में (सन् 1910 से) प्रिटोरिया सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियाँ बढ़ती गई हैं।

परन्तु इसके ठीक समानान्तर 'न्याय और स्वतंत्रता' की आवाज भी निरन्तर तेज होती गई। सन् 1912 में 'अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस' की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक प्रतिरोध जारी है। मुट्ठी भर बुद्धि-जीवियों द्वारा 'प्रस्ताव पारित कर' अंग्रेजी हुकूमत के दरवाजे गुहार लगाने वाला यह प्लेटफार्म अब एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। सन् 1961 के सेल्सबेरी कांड के बाद (जिसमें निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोरे सिपाहियों ने गोलियाँ बरसाई थीं) जब 'अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस' पर प्रतिबंध लगा और आंदोलन के नेता नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर आजीवन कैद की सजा दे दी गई तो अफ्रीकी युवा मानस का गुस्सा फूट पड़ा। 'अपील और दलील' की राजनीति करने वाली 'अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस', की तेवर में तीखा बदलाव आया। 'ईंट का जवाब पत्थर' से देने की नीति प्रारम्भ हुई। इस पृष्ठभूमि में हिंसात्मक प्रतिरोध को स्वीकृति मिली। सन् 1976 में स्वाटों का छात्र-विद्रोह और सन् 1980 में मजदूरों की लम्बी हड़ताल से द. अफ्रीकी सरकार की नींद हराम हो गयी। बदहवास हुकूमत निरपराध-निर्दोष लोगों के खून से 'आजादी की आंच' को बुझाने पर आमादा है। दुस्ताहसी नस्लवाद पड़ोसी समर्थक देशों—जिम्बाम्बे, मोजम्बिक आदि पर भी आये दिन सैनिक आक्रमण कर बैठता है। व्यापारिक और राजनीतिक कारणों से ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारें पूरी तरह प्रिटोरिया सरकार के इस उन्माद को हवा देती हैं। शायद उन्हीं शक्तियों के बल पर 1984 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में गठित 'सम्पर्क समिति' (जिसे प्रिटोरिया सरकार और अ. नेशनल

कांग्रेस' के बीच मध्यस्था करने का दायित्व दिया गया था) के प्रस्तावों को द. अफ्रीका ने मानने से इन्कार कर दिया। विश्व जनमत अपमानित होकर रह गया। इसके बावजूद अब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नस्लवाद और रंगभेद के खिलाफ आवाज तेज हो रही है। चाहे वह 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' हो अथवा राष्ट्रकुल सम्मेलन सर्वत्र प्रिटोरिया सरकार को अलग-थलग करने की मुहिम जारी है। हाल में हरारे (जिम्बाम्बे) में सम्पन्न गुटनिर-पेक्ष देशों के सम्मेलन के सर्वसम्मत फैसले से यह स्पष्ट है कि अमेरिका और ब्रिटेन चाहकर भी रंगभेद विरोधी आंदोलन की आंधी को नहीं रोक सकेंगे।

अपना भारत भी रंगभेद विरोधी आंदोलन का प्रबल समर्थक है। गोरी नस्लवाद प्रिटोरिया सरकार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध का मामला हो अथवा उसके राजनैतिक सांस्कृतिक बहिष्कार का प्रश्न, हम भारत के लोग सदैव आगे रहे हैं। सन् 1946 से ही (स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व) भारत ने द. अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ रखे हैं। पिछले दिनों यहीं दिल्ली में बोलते हुए 'अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस' के प्रतिनिधि श्री मूसा मोल्लाह ने कहा था, "हमने काफी दूरी तय कर ली है, नस्लवाद और रंगभेद के खिलाफ जंग में हम जीत के बिल्कुल निकट हैं। जरूरत इस बात की है कि जिन राष्ट्रों का समर्थन हमें मिलता रहा है, वे अपना सहयोग बनाये रखें। ताकि हमारे सेनानियों का मनोबल बना रहे।"

आशा है, जल्द ही एक और देश स्वतंत्रता की रोशनी में उन्मुक्त भाव से विचरण कर सकेगा। आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और गुलामी रहित स्वस्थ-सामाजिक व्यवस्था सौंप सकेगा। आजाद भारत के हम आजाद छात्रों की सारी शुभकामनाएँ और समर्थन उनके साथ हैं।

—सं. स.

## साक्षात्कार

[‘छात्र शक्ति’ के प्रतिनिधियों ने चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत की है। जगह कम होने के कारण हम सभी साक्षात्कार को प्रकाशित नहीं कर कुछ चुने हुए साक्षात्कार को पाठकों के सामने रख रहे हैं।]

**राजधानी कॉलेज : ‘विजय के साथ संघर्ष’ :**

राजधानी कॉलेज छात्रसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अजय गुप्ता ने प्रशासन के छात्र-विरोधी रवैये के खिलाफ एक लोकप्रिय आंदोलन चलाया जिसे समाचार-पत्रों ने काफी महत्व दिया। “छात्रों के नामांकन में हुए भेदभाव को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम तो छात्र संघ चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी आवाज ने प्रशासन को बता दिया अब छात्र-विरोधी हरकते हम नहीं सह सकते हैं—” कहते हैं अजय गुप्ता। वि० वि० छात्र संघ के सचिव श्री नरेन्द्र टंडन ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी।

**कला संकाय : ‘छात्र राजनीति बदलने का संकल्प’**  
कला संकाय छात्र संघ में श्री एस० एस० चौधरी अध्यक्ष, प्रवीण कुमार उपाध्यक्ष, भी० के० संदेश महासचिव, और के० के० शुक्ला सहसचिव बने। भी० के० संदेश के अनुसार, “परिपद भले अध्यक्ष पद का चुनाव हार गया पर पहली बार राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए जिसका श्रेय इसके अध्यक्षीय उम्मीदवार को जाता है। मैं छात्रों के बीच राजनीतिक नेताओं के दखलंदाजी के खिलाफ हूँ। “हमारे यूनियन कार्यालय में असामाजिक तत्वों का पहले बोलबाला था अब हमने उन्हें विस्थापित कर दिया अब और कुछ बदलना है”—कहते हैं भी० के० संदेश।

**हिन्दू कॉलेज छात्र राजनीति : नया आशाम**

हिन्दू कॉलेज छात्र संघ चुनाव का परिणाम परिपद के लिए काफी संतोषजनक रहा :

प्रधानमंत्री पद पर श्री देश रत्न निगम, को सफलता मिली। अन्य पदों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं :

आलोक रंजन (एस. ए. एफ. सचिव), प्रतुल नाव (सांस्कृतिक सचिव), राजेश मेनन (पत्रिका प्रभारी) और धनंजय कुमार एवं संदीप गुप्ता (सेन्ट्रल काउंसलर)।

आलोक रंजन के अनुसार, “एस. एफ. एफ. लाइब्रेरी की दयनीय हालत को सुधारना मेरा पहला काम होगा।”

धनंजय कुमार ने यू. स्पेशल बसों के चलाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है।

श्री निगम के मुताबिक “हम कॉलेज में बौद्धिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएँ तथा छात्र संघ को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे।”

**देशबंधु (सांध्य) कॉलेज : छात्रहित की लड़ाई**

छात्र संघ के सचिव राजीव दुग्गा के अनुसार, “हमारी कोई राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है। हम छात्र-हितों के लिए छात्र संघ का उपयोग करेंगे। महाविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।”

**इन्द्रप्रस्थ कॉलेज : छात्राश्रमों की समस्याएं कम नहीं**

इस कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्षता सुश्री शुभा का कहना है, “छात्राश्रमों की समस्याएं दबकर रह जाती हैं। अब हम इसे जोरदार ढंग से रखेंगे।”

**दौलत राम कॉलेज : समस्या ही समस्या**

छात्र संघ की उपाध्यक्षा कुमारी तुलिका अपने महाविद्यालय की छात्राश्रमों को जुभाऊ रूप देना चाहती हैं। “समस्याओं से हम लड़ेंगे, संघर्ष में विजय भी होगी।”

छात्र संघ की कोषाध्यक्ष सुश्री दीपा भट्टाचार्य, के अनुसार “शैक्षणिक समस्याओं के प्रतिरिक्त भी अनेक समस्याएं हैं जिसके लिए हम मिलजुलकर समाधान ढूँढ रहे हैं।”

रिपोर्ट :—संजय चौधरी, समीर, आलोक,

लेखन :—राकेश सिन्हा।

## **New Education Policy : Critical Survey**

Does the education Policy 1986, really proposes to declare an action plan for its implementation? This is a very valid question which raises doubt about the real potentialities of the education Policy.

The education policy 1986, in a round about manner merely restates the old and worn out ideas. Most of the recommendations of the Kothari Commission (1964-66) and the National Education Policy of 1968 are just revived and presented in a new grab of papers, which speak of high aspirations, without adequate resources. By and large, the 1968 Policy was never implemented. The 1986 Policy unequivocally accepts this failure.

The success of a Policy is determined by its implementation not merely by its content. The policy severely suffers from certain deficiencies which cannot be ignored anymore. We shall study the goals and content, analyse them in the light of truth and data, and thus draw conclusions.

The Policy is not founded on any Philosophy of life or thought. It has not visualised the Indian Society and urges for new technology to take the country into the 21st century. It gives the hollow slogans of "Universalisation of education and Vocationalisation" without any available infrastructure, 10% Villages don't have a school; 2/3 of the Nations' Population is illiterate; 41.5% Primary schools are without black-boards, and 72% without libraries; not to talk of latrines and loavatories.

The Policy does not reflect any urge to bring about fundamental transformation in character of education. Education should be made rural oriented. The co-existence of public schools with the common school system is against the principle of equality of Education.

(Abridged from O.P. Kohli's work by Sanjay Chowdhary)

The Policy talks of consolidation, not expansion. Thus several proposals are contradictory and there is an absence of a rational determination of priorities.

The new Education policy asserts adult education, two room and two-teacher schools, teacher training programmes, three language formula, establishment of the National Education Services, and an effort to raise the expenditure on education to 6% of the National Income; while the experience shows we have never gone beyond 3%... To make the Policy a success, ABVP has suggested the creation of an autonomous National Education Foundation and allotment of 10% of National Income on Education.

The Policy omits the complex problem of medium of instruction. Its ESCAPIST character is very much evident in the light of the fact that it does not even refer to the eradication of politics and corruption, banning of public schools, and stopping the brain-drain etc. It lays emphasis on the accountability of teachers and institutions, but not on autonomy. Important matters such as moral education, patriotism and national pride have been completely neglected.

Education now is in the concurrent list and the central government has assumed greater responsibility for educational development under the new education policy. Now, the educational change will depend on three things:— resources, implementation machinery and political will.

No policy by itself is patently bad. The test of it lies in implementation. The earlier policies had failed because of the absence of planning, commitment and dedication. Are these elements tangible for the implementation of the 1986 policy? Assertions, unsupported by a powerful urge deepen the disappointment.

## Think and Grow Rich

Think and grow rich is one of the most influential and inspiring books of all time in pointing the way to personal achievements. It formulates a two way path to success—material and spiritual satisfaction.

Think and grow rich is pre-eminently a 'what-to-do and how-to-do-it' book. The values projected in it are based on the experiences and experiments of great men, who harmonised friendships, family relations, sympathy and understanding between associates to attain riches. Riches—which cannot always be measured in terms of money!

The book begins with a chapter on thoughts. Thoughts, which are so essential for the survival of man. The very thought of the universe makes this universe exist. For the development and success in life, we have to think our way. Thoughts are the things we desire; and the desire should be definite. An intangible impulse of thought can be transmuted into material rewards. One sound idea is all you need. And once set the goal, stake everything to attain it.

Success comes to those who become success conscious. Failure comes to those who indifferently allow themselves to be failure conscious. Therefore, be success conscious and always think of success. Apply the principle of success. **WE ARE THE MASTERS OF OUR FATE THE CAPTAINS OF OUR SOUL, BECAUSE WE HAVE THE POWER TO CONTROL OUR THOUGHT,** amidst the circumstances of life which harmonise the nature of our thoughts. Magnetise

your mind with intense desire for riches. Desire drives us to create definite plans for acquiring things of our thought. Desire is the starting point of all achievements. Whatever the mind of man conceive and believe it can achieve. Only the desire should not be a 'hope' or a 'wish', but should be keen, pulsating desire. Definite! Desire does not recognise failure. Determination to have it and the belief to possess with the definiteness of purpose is real desire.

Faith is the head chemist of mind. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. Both poverty and riches are the offspring of thought. Faith is a state of mind which may be created by affirmation. It is developed at *will*. It is a voluntary development. No one was ever 'DOOMED' to bad luck. Faith can be intensified by Self-Suggestion, which generates confidence and destroys negative thinking.

Every adversity, every failure and every heartache carries with it the seed of a greater benefit. The way is through personal experience and observation. We have an inherent potential power for it.

The author proceeds with Organised Planning—the crystallization of desire into action and suggests many ways and means to approach. It is only when the plan of action is prepared that we take Decision. Decision can change the whole history.

How many times you may fail, but keep trying. Persistence, i.e., the sustained effort



necessary to induce faith, ensures the attainment of objective. CLIMB OVER YOUR FAILURES. CASH OVER THE MENTAL INERTIA, TRAIN YOURSELF TO BE PERSISTENT. DO NOT FEAR CRITICISM. MASTER ALL DIFFICULTIES! This is the message of Napoleon Hill.

The author discusses the forces which drive a man and govern his success. What he calls the 'power of the master mind' is the way to multiply brain power and positive emotions.

Nepoleon Hill ends up this classic work by enumerating the 'ghosts' that stand in our way and yet remain unobserved many times. Those who shed all fear and cut loose all chains, invent themselves, their success and their fortune.

—SANJAY CHOWDHARY

Book—Think and grow Rich Author—  
Nepoleon Hill. Price—Rs. 35/-Page-254  
Publishers—D.B. Taraporevale sons and  
Co. P.Ltd.

## News Diary

The 32nd All India Annual Convention of Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad is to be held on 27 - 29, Dec. '86 at Vishakhapatnam (Andhra Pradesh). Member activists from all over the country will participate in this convention.

\* \* \* \* \*  
The sixteen members DUSU Executive Council get constituted as the eleven student representatives from 51 DUSU affiliated colleges declared elected on 25th Sept. '86. The four DUSU office-bearers and the outgoing President are ex-officio members to this council. According to DUSU constitution, this is the strongest body, who deals with financial & budgetary matters of the Union.

\* \* \* \* \*  
Blind students, seeking job and justice, are on strike since 1st Sept. '86. They have been

demanding one percent reserved quota in different govt. jobs; unemployment allowances; absorption of all blind students with M.A. M.Ed. degree and preference in recruitment to the teaching posts in blinds' schools.

\* \* \* \* \*  
Desbandhu College unit of ABVP organised an essay and declamation contest on 24th Sept. '86 in college premises. Their respective theme/topic were 'Punjab Problem' & 'Computer Rule'.

\* \* \* \* \*  
The twenty fifth state conference of Rajasthan is scheduled to be held on 27-28 Sept. '86. Sri Prabhash Joshi editor Jansatta is the Chief Guest and Sri Madan Das, All India organising secretary will be the main speaker.

## National Convention on Sri Lanka : A Report

A national convention on Sri Lanka was organised by Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad, Tamilnadu state unit in Madras city on 10th Aug. '86 as per the decision taken by the NEC of ABVP at Indore (M.P.). Nearly 350 participants including several prominent personalities from different organisations/parties viz TULF, BJP, DMK, TELO, PLOTE, RSS, etc. took part in this convention. The statement of consensus adopted by the delegates of the convention is as follows :—

1. Early settlement of the Sri Lankan crisis is imperative not only from the point of view of the establishment of peace in the island, but also in the larger interest of our own national security of preserving the Indian Ocean area as a zone of peace.
2. The Tamil people of Sri Lanka have every right to live as free and equal citizens of Sri Lanka. Denying them the basic rights of citizenship and condemning them to the status of second class citizens, is totally unacceptable.
3. This convention while sympathising with the demand of Sri Lankan Tamils for Eelam, is of the opinion that, political solution to the problem should be worked out on the basis of concept of united Sri Lanka and on the cardinal principles of justice and equality. A political solution to the problems of a pluralist society like that of Sri Lanka is possible only on the basis of democratic devolution of political and economic power whereby the rights of every citizen and all communities are assured without any discrimination on grounds of caste, creed, languages or race. Necessary legal provisions consequences upon the agreement

should be incorporated in the Sri Lankan Constitution:

4. This Convention condemns the state-terror let loose by the Sri Lankan government to annihilate the Tamils. Any political solution will be useless unless violence ends. The Government of Sri Lanka must take immediate steps to achieve this. Until a political solution is worked out Sri Lankan government should undertake not to induct foreign military personnel.
5. A large number of Tamil patriots are languishing in the jails of Sri Lanka without any trial. Most of them are men and women in the prime of their life. All of them must be released forthwith or else brought to trial on specific charges. Human rights and humanitarian organisations like the International Committee of the Red Cross and Amnesty International should be permitted to visit these detenus and see their conditions.
6. The draconian, so-called anti-terrorist laws, which have come to be used as an instrument of oppression by the government, must be withdrawn.
7. The internecine fight among Tamil groups is a factor which hurts the cause of Tamil people. This fractricidal violence must stop. Killing of innocent citizens must be categorically denounced by all.
8. The Northern and Eastern Tamil majority provinces must be merged to constitute one united Tamil province. Formation of such a linguistic province will give them a sense of security and enable them to live as equal citizens, enjoying full rights of

citizenship. The demand is justified and must be conceded.

9. The Indian Government owes it to the people of India and the people of Lanka to see that an early political solution based on wellknown federal principles is hammered out and duly implemented in letter and spirit. The government should make the Sri Lankan government see reason and warn it against any attempt at a military solution.

10. The convention appoints a standing committee consisting of following members to take necessary steps to educate and mobilise public opinion throughout the country in support of the cause of Sri Lankan Tamils.

Sri K.R. Malkani (Delhi), Sri Mahesh Chandra (Delhi), Prof. Bal Apte (Bombay), Sri H. Dattatreya (Bangalore), Sri S. Sri Nivasan (Madras) and Sri K.N. Govindan (Delhi) - Convener.



क्या बात !

### SUBSCRIBE

#### RASHTRIYA CHHATRA SHAKTI

Please enrol me for annual membership of the magazine CHHATRA SHAKTI. I will pay Rs. 10/- as subscription, when I receive the first issue.

NAME .....

ADDRESS .....

SEND NO MONEY NOW

ABVP-16/3676, HARDHYAN SINGH ROAD  
REGARPURA, KAROL BAGH, DELHI-5

## 'SEIL' A Project Of National Integration.

Never before was our country so much in the grip of secessionist forces. Emotional integration, which is the mainstay of national unity, is weakening day by day. Mainly the younger generation is coming handy for the secessionist forces. East, West, North and South, go any where and the lurking dangers of the divisive forces are found at work.

Emotional integration, a real feeling of oneness which will make everyone rise above the linguistic, regionalistic or-communal considerations is the real need of the hour.

Students Experience in Inter-State Living (SEIL) a voluntary organisation sponsored by the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) is trying to achieve the same-the most elusive emotional integration. In 1966, when a group of ABVP workers visited North-East India, the urgent need to evolve emotional integration was seriously felt. It was in the same year that SEIL was established.

For obvious reasons, it was also observed that the border areas of our far-flung nation are more prone to the danger of secessionism. Geographical distance leading to psychological alienation has already caused many harms. All this has resulted into a lack of cultural rapport between the people staying in the heartland and those belonging to the border areas.

With a view to bridging the psychological distance SEIL has taken up several multipronged projects and programmes during the last 20 years. Cultural exchange tours, involving an arrangement of staying in local host families is the main activity of the SEIL. So far around

300 students from the border provinces, mainly from the North-East have participated in such tour programmes. While almost an equal number of students from other provinces have visited the far-off border states. It remains a unique occasion, for the participants to stay in a family with a different life style, and it gives them a chance to have a first-hand experience of the unity in diversity.

So far students from all the North-Eastern provinces except Tripura and Mizoram and also from Maharashtra, Goa, Karnataka, Andhra Pradesh and Gujarat have participated in these tours.

### Andaman Yatra

SEIL celebrated the International Year of the Youth-1985 by opening new avenues for its activity. A group of 15 students and youths from Maharashtra and Goa visited Andaman & Nicobar islands. To mark the distinctness of this tour which was not an excursion but was a socio-cultural exchange tour, an orientation camp was organised before the tour and a feedback camp at the end of the tour.

### Activities of the SEIL At a glance

- \* Cultural Exchange Tours to and from border areas.
- \* Personality Development Camp for border area students, mainly tribals.
- \* Presentation of informative audio-visuals on North-East in social get-togethers.
- \* Get-togethers of North-Eastern students studying at prominent educational centres.